VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 08 SEP 2022 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1835)

Name of Candidate	Vikash Senthiya		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	398329
Center	MN	Date	08/09/22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. The withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India threatens the spirit of cooperative federalism in India. Discuss.
(150 words) 10

भारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेना भारत में सहकारी संघवाद की भावना के लिए खतरा उत्पन्न करता है। चर्चा कीजिए।

भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है जहाँ केन्द्र के साथ राज्यों को भी ~~विभिन्न~~ विषयों पर स्वायत्तता प्रदान की गई है।

लेकिन वर्तमान में CBI के मुद्दे पर केन्द्र-राज्य टकराव देखने की स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे - केन्द्र व पश्चिम बंगाल राज्य

राज्यों द्वारा CBI से सामान्य सहमति वापस लेने का कारण

1- राज्यों का आरोप है कि CBI के माध्यम से राज्य की स्वायत्तता कम करने का प्रयास

2- CBI खुद राजनीतिकरण का शिकार है।

3- विरोधी पार्टी वाले राज्यों में CBI का प्रयोग अधिक देखने को मिला है।

4- राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु CBI का प्रयोग

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5- CBI की स्वायत्तता स्वयं संदेहास्पद
SC ने 'पिंजरे में बंद तोता' कहा CBI को।

केन्द्र का तर्क

1- राज्यों के प्रशासन की विफलता में केन्द्र का हस्तक्षेप आवश्यक
2- भ्रष्टाचार जैसी संस्कृति को तथा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु CBI का प्रयोग आवश्यक
3- संवैधानिक मूल्यों व नैतिकता को बनाए रखने हेतु

वस्तुत: संघात्मक शासन को सुदृढ़ बनाने हेतु दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर CBI को अधिक स्वायत्त व प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

देश को आर्थिक विकास के पथ पर ले जाने, लोककल्याण तथा संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए केन्द्र राज्य संबंधों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए।

2. Stating the sources of finance for local self-governments in India, suggest ways to strengthen their financial position. **(150 words) 10**

भारत में स्थानीय स्व-शासी सरकारों के लिए वित्त के स्रोतों का उल्लेख करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय सुझाइए।

73rd तथा 74th संविधान संशोधन के माध्यम से शासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय शासन की अवधारणा को लागू किया गया।

व्यवहार में देखा गया है कि स्थानीय सरकारों को अपने कार्यों की पूर्ति में वित्त की कमी का सामना करना पड़ता है।

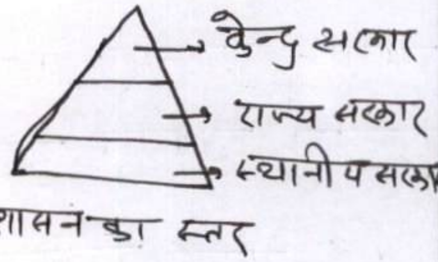

स्थानीय शासन के वित्त के स्रोत

- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों द्वारा कर वितरण
- अनु. 275 के तहत मिलने वाला विधिक अनुदान
- सरकारी योजनाओं के तहत प्राप्त राशि जैसे - मनरेगा
- स्वयं द्वारा लगाए गए कर जैसे - मनोरंजन कर आदि

स्थानीय शासन की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण

1- राज्य द्वारा धन आवंटन सिद्धांत का उचित अनुपालन न करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2- स्थानीय सरकारों का अकुशल वित्तीय प्रबंधन
3- स्वयं के कर राजस्व स्रोतों को विकसित करने की इच्छाशक्ति का अभाव
4- राज्यों पर अत्यधिक निर्भरता

वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय

1. स्थानीय सरकार में कुशल पेशेवरों द्वारा वित्तीय प्रबंधन सुधारने पर बल

2- 14वें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय शासन को दिए गए धन के आधार पर राज्यों को धन का आवंटन

3- स्थानीय सरकारों द्वारा स्वयं के कर स्रोतों तथा राजस्व जुटाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना → कुछ क्षेत्रों में कर लगाना
→ अनुपयुक्त भूमि को निजी क्षेत्र के सहयोग से मुद्रीकृत करना → चारागाह कर

4- राज्यों द्वारा पर्याप्त व समय पर धन आवंटन
5- योजना लागू करने में अधिक स्वायत्तता

स्थानीय शासन लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाते हैं अतः इनकी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति आवश्यक है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Cabinet Committees play an important role in reinstating collective responsibility and principle of homogeneity of the Executive in the Indian Parliamentary system. Elucidate. **(150 words) 10**

भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियां सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्पष्ट कीजिए।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ कैबिनेट के सदस्यों को मिलाकर विभिन्न विषयों पर तीव्र व प्रभावी निर्णय लेने के लिए गठित की जाती हैं। अधिकांश समितियों में प्रधानमंत्री अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं।

जैसे - आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति

कैबिनेट समितियों की भूमिका

1- सरकार के निर्णय तीव्र व खुले रूप से लिए जाते हैं।

2- कैबिनेट सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर क्योंकि यहां दलबदल कानून नहीं लागू होता है।

3- निर्णयों में सभी सदस्यों की सहभागिता बढ़ती है और सभी उस निर्णय के प्रति उत्तरदायी जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के अनुरूप।

4. सदस्यों के मतभेदों का समाधान कर विभिन्न मुद्दों पर एकमत से सरकार में एकरूपता सुनिश्चित होती है।

5. पर्याप्त विमर्श व विशेषज्ञों से परामर्श के कारण प्रभावी निर्णय व नीति निर्माण

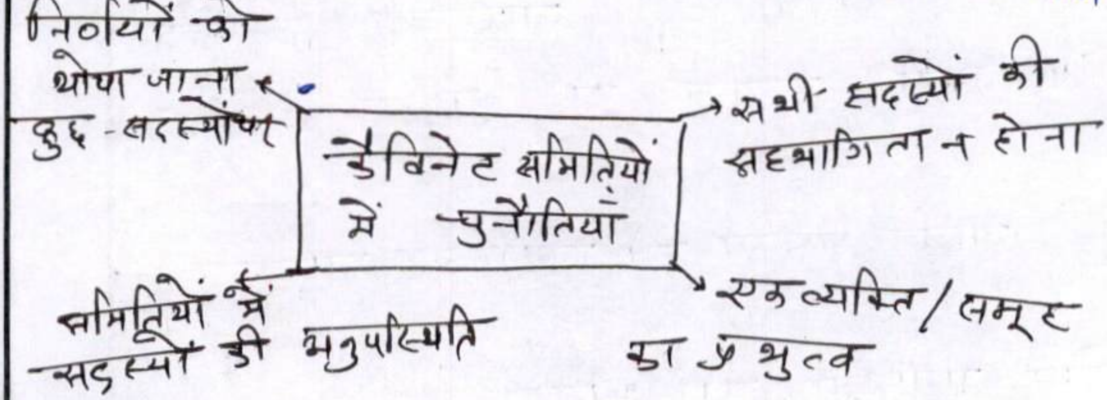

अत: लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप कैबिनेट समितियों में प्रभावी विचार विमर्श व सहभागिता सरकारी कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. There is a need to overhaul the public procurement and project management (PPPM) framework of India for faster, efficient and transparent execution of government projects. Comment.

(150 words) 10

सरकारी परियोजनाओं के तीव्र, कुशल और पारदर्शी निष्पादन के लिए भारत के सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

भारत एक लोककल्याणकारी राज्य का स्वरूप धारण करता है और यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई हेतु अनेक परियोजनाएँ चलाई जाती हैं। जैसे - मनरेगा, आयुष्मान भारत, खाद्य सुरक्षा मिशन आदि।

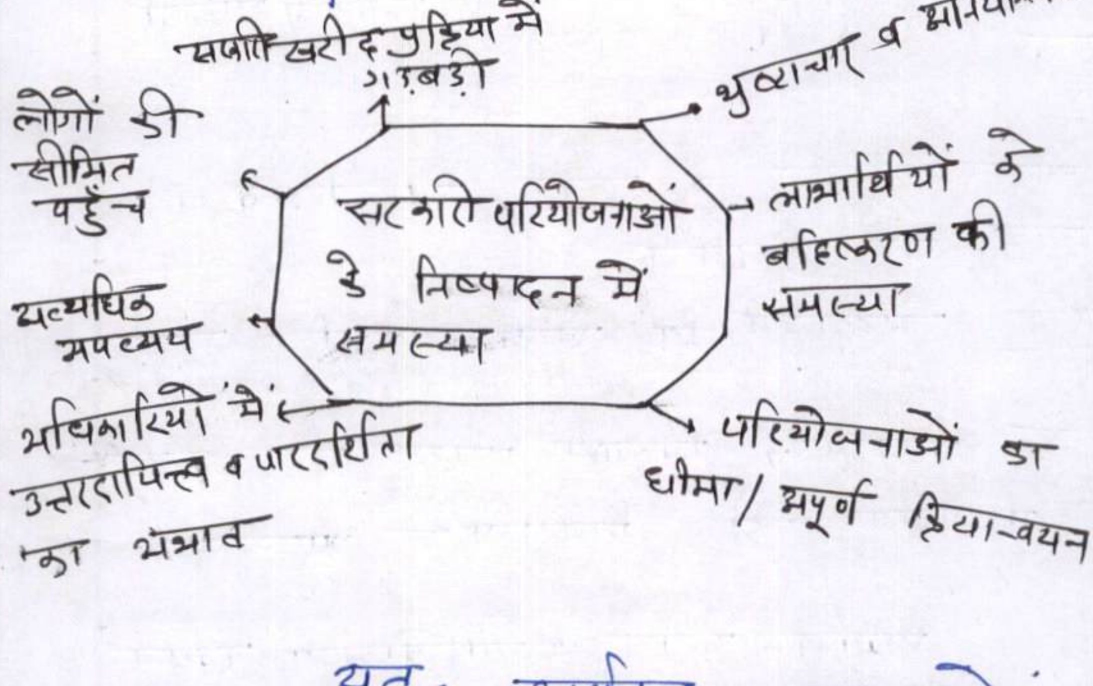

अतः उपर्युक्त समस्याओं के मद्देनजर सार्वजनिक खरीद व परियोजना प्रबंधन के ढाँचे में निम्न सुधार किए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जाने चाहिए —

1- सरकारी खरीद एक पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा जैसे - GEM पोर्टल - ऑनलाइन खरीद

2- खरीद की प्रक्रिया तीव्र तथा गुणवत्ता युक्त वस्तुओं की खरीद

3- परियोजनाओं निर्माण - साक्ष्य आधारित नीति के आधार पर

4- e- गवर्नेंस के प्रयोग से परियोजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से अंतिम लाभार्थी तक

5- सोशल ऑडिट के द्वारा उत्तरदायित्व में वृद्धि का प्रावधान
जैसे - मेघालय में सोशल ऑडिट कानून

6- एक स्वायत्त व निष्पक्ष संस्था द्वारा खरीद व परियोजना की निगरानी व मूल्यांकन

समुचित खरीद व परियोजना प्रबंधन ढाँचा सरकारी धन के अपव्यय को रोककर सामाजिक कल्याण व सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Adequate measures are required to overcome the challenges and vulnerabilities associated with undertaking social accountability initiatives and institutionalising them. Elaborate. **(150 words) 10**

सामाजिक जवाबदेही पहलों को शुरू करने और उन्हें संस्थागत बनाने से जुड़ी चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपायों की आवश्यकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

सामाजिक ऑडिट ~~जवाबदेही~~ का आशय योजना के लाभार्थियों द्वारा योजना के प्रभावों का मूल्यांकन करने से है। यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की एक विधि है। सोशल ऑडिट के माध्यम से सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

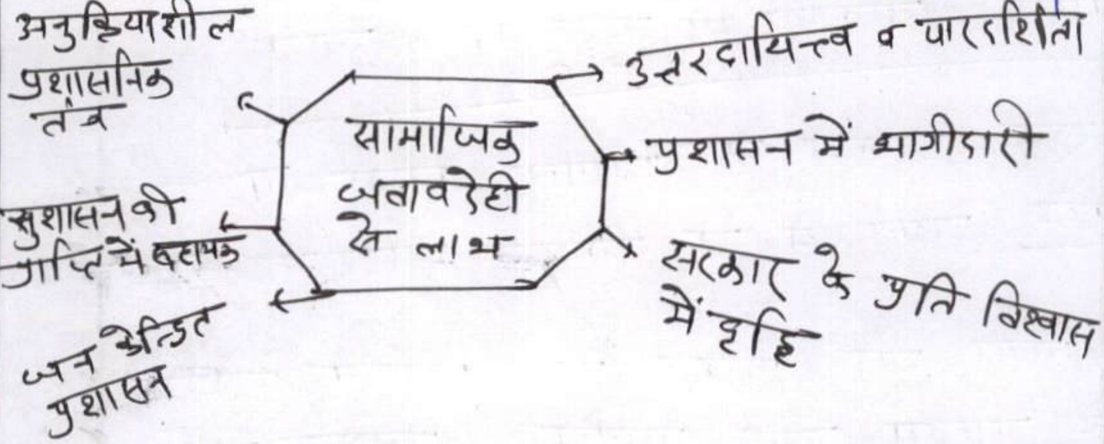

सामाजिक जवाबदेही पहलों को शुरू करने व संस्थागत बनाने से जुड़ी चुनौतियाँ

1- प्रशासन में भ्रष्टाचार की संस्कृति तथा पारदर्शिता व उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2- सरकारी नीति में कमी - योजना से उत्पन्न परिणामों के प्रति उत्तरदायित्व लेने की व्यवस्था नहीं।

3 - सामाजिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए जनता में कम जागरूकता व सीमित जनसहभागिता

4 - संस्थागत बनाने हेतु - राजनीतिक इच्छा की कमी
↳ विधायी समर्थन का अभाव

सामाजिक जवाबदेही की सुदृढ़ता के उपाय

1- एक कानून का निर्माण करना चाहिए
जैसे मेघालय ने सोशल ऑडिट एक्ट बनाया।

2- लोगों को जागरूक तथा सिविल सोसाइटी के माध्यम से सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल

3- प्रभावी व अनुक्रियाशील शिकायत निवारण तंत्र

4 - प्रशासन में पारदर्शिता जैसे नैतिक मूल्यों का समावेश

सामाजिक जवाबदेही योजना के वांछनीय परिणामों को प्राप्त करने तथा सुशासन की स्थापना में सहायक होती है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. In view of the recent Parliamentary Standing Committee report, discuss the issues faced by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) and suggest measures that can be adopted to strengthen it. **(150 words) 10**

एक संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए और इसे मजबूत बनाने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. While the Mid-Day Meal scheme was aimed at fulfilling the nutritional needs of students, it is far behind in achieving this objective. Discuss. Also, suggest remedial measures in this context. **(150 words) 10**

यद्यपि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था, किंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह काफी पीछे है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए स्कूलों में मिड-डे-मील योजना प्रारंभ की गई है।

उद्देश्य -
- बच्चों में पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा हिडन हंगर की समस्या को दूर करना
- स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि करना

लेकिन वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि यह अपने उद्देश्यों को पूर्ण नही कर पायी है- जैसे

1- ग्लोबल हंगर इंडेक्स - भारत का स्थान 101 वॉं

2. NHFS-5 - बाल ठिगनापन (stunting) - 35.5%
बाल दुबलापन (wasting) - 19%
अल्पवजनी बच्चे - 32%

③ 70% किशोरियां एनिमिया से पीड़ित है।

④ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर GER अभी भी वैश्विक औसत से कम।

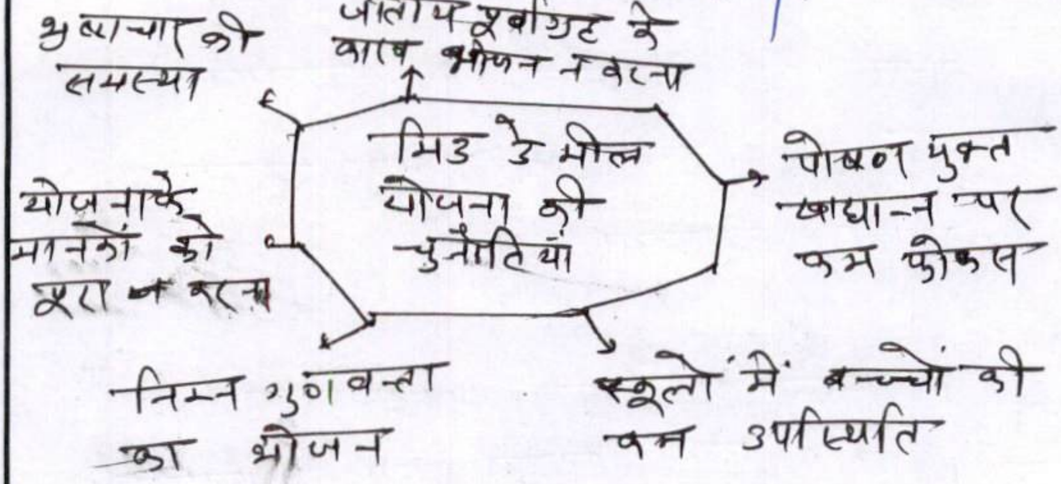

उपचारात्मक उपाय

1- अधिक प्रोटीन युक्त भोजन जैसे- फोर्टिफाइड चावल

2- स्कूलों के औचक निरीक्षण द्वारा गुणवत्ता की जाँच

3- सोशल ऑडिट के द्वारा भ्रष्टाचार को कम करना

4- CCTV, GPS, DBT आदि तकनीकों द्वारा प्रभावी वितरण

5- गरीबी व बेरोजगारी दूर करने के प्रयास

बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति देश को सशक्त कर बेहतर भविष्य का निर्माण करती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Sexual and reproductive health and rights (SRHR) remain critical for the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs). In this context, discuss the impediments in the fulfilment of SRHR in India. Also, mention the steps that can be taken in this regard. **(150 words) 10**

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, भारत में SRHR की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार से तात्पर्य प्रजनन करने वाली महिला की स्वस्थ स्थिति, प्रजनन संबंधी तथा परिवार नियोजन संबंधी निर्णयों में स्वायत्तता से है।

भारत में यौन व प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति

1- केवल 14% महिलाएँ परिवार नियोजन में निर्णय लेने में स्वायत्त
2- 70% महिलाएं में प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियाँ
3- किशोरावस्था गर्भधान - हालांकि इसमें कमी आई किन्तु अभी 6%
4- केवल 67% महिलाए गर्भ निरोधकों का प्रयोग करती हैं।

SRHR की प्राप्ति में बाधाएँ

1- सामाजिक - महिलाओं की समाज में निम्न स्थिति
- लड़के को अधिक प्राथमिकता, लड़कियों के स्वास्थ्य पर सीमित खर्च

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- विवाह पश्चात पर महिला के शरीर पर अधिकार मानने की पितृवादी सोच

प्रशासनिक - स्वास्थ्य अवसंरचना अपर्याप्त
- 70% हॉस्पीटल] शहरों मे केन्द्रित
- 75% मेडीकल] शहरों मे केन्द्रित
- न्यून महिला स्वास्थ्यकर्मी
- रोगी - डॉक्टर अनुपात 1:1456

अन्य - ① सामाजिक कलंक - इस प्रकार की बातों पर चर्चा करने पर
② यौन शिक्षा का अभाव
③ स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच
④ जागरूकता की कमी।

उठाए जा सकने वाले कदम

1. आशा कार्यकर्ता, NGO, SHGs आदि के द्वारा यौन शिक्षा प्रदान करना
2- स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार व स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण
3- मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत आदि का प्रभावी क्रियान्वयन

वर्ल्ड बैंक के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की 10% भागीदारी GDP को 27% तक बढ़ा सकती है। अतः महिलाओं का स्वस्थ होना आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. State the functions of the United Nations Human Rights Council. Also, discuss the issues faced by the Council in the promotion and protection of human rights around the globe. **(150 words) 10**

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण में परिषद द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के कार्य

① विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना

② मानवाधिकारों को बढ़ाने वाले सिद्धांतो का प्रचारित करना

③ मानवाधिकारों पर विभिन्न राष्ट्रों की सहमति से घोषणापत्र जारी करना

④ मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में UNSC में पीस कीपिंग फोर्स भेजने का आवाहन करना।

चुनौति

1- विभिन्न देशों द्वारा मानवाधिकारों की अलग - अलग व्याख्या

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2- UNHRC की सिफारिशों की अनदेखा करना
3- UNHRC के पास कोई कार्रवाई की शक्ति नहीं।
4- UNSC में राजनीतिकरण के कारण निर्णय नहीं।

UNHRC विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के माध्यम से एक समावेशी व शांतिपूर्ण समाज की कल्पना करती है। अतः इसे आवश्यक शक्तियाँ देते हुए अपेक्षित सुधार किए जाने चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. West Asia is an important strategic region for India with profound geo-political and geo-economic significance. Discuss. **(150 words) 10**

अत्यधिक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महत्व के कारण पश्चिम एशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। चर्चा कीजिए।

पश्चिम एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। बदलते भू-परिदृश्य में ऊर्जा सुरक्षा तथा वैश्विक शांति स्थापना के कारण पश्चिम एशिया का भारत के लिए महत्त्व बढ़ जाता है।

पश्चिम एशिया का भारत के लिए महत्त्व

1- ऊर्जा सुरक्षा

भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा हेतु 80% से अधिक तेल का आयात जिसमें से 70% पश्चिम एशियाई देशों से। तथा TAPI परियोजना का विकास

2- आर्थिक - व्यापार की दृष्टि से इन देशों का महत्त्व
- भारतीय निर्यात का अत्यधिक इन्हीं देशों को जाता है।

3- डायस्पोरा - भारत की लगभग 8-10 मिलियन जनसंख्या पश्चिमी एशियाई देशों में
- जिससे भारत को बड़ी मात्रा में रेमिटेंस प्राप्त

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4- सामरिक - भारत, शस्त्रों के लिए इजरायल पर निर्भर है।

5- रणनीतिक - चीन का बढ़ता प्रभाव - BRI के माध्यम से → अत: इसे संतुलित करने हेतु
→ कनेक्ट सेंट्रल एशिया की नीति के क्रियान्वयन हेतु जैसे- ईरान में चाबहार बंदरगाह
→ INSTC के प्रभावी संचलन हेतु

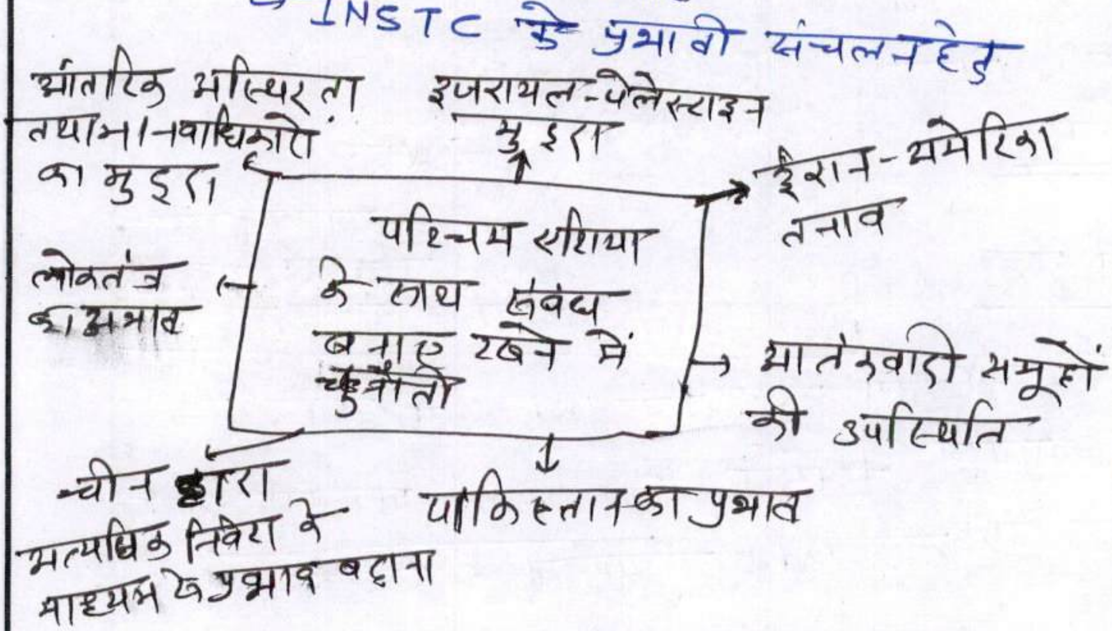

वर्तमान में भारत डी-हाइफनेशन नीति के तहत विदेश नीति में डी-हाइफन-नीति का प्रयोग करते हुए संबंधों को मजबूत कर रहा जिसका उदाहरण I2U2 का गठन तथा अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान से तेल तथा अफगानिस्तान से वार्ता के संबंध में दिखा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Disenfranchising prisoners desecrates a cherished value in a democracy i.e. 'right to vote', which should be guarded earnestly. Discuss in the light of The Representation of The People Act, 1951. **(250 words) 15**

कैदियों को मताधिकार से वंचित करना वस्तुतः लोकतंत्र के एक प्रशंसनीय मूल्य, अर्थात् "मतदान के अधिकार" का अपमान करना है, जिसकी गंभीरतापूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारत में संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई गई है तथा नागरिकों को सार्वभौमिक व कानूनी मताधिकार के माध्यम से उनकी सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

लेकिन मताधिकार निरपेक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता है। RPA, 1951 के तहत इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जैसे- कैदियों को मताधिकार से वंचित करना।

कैदियों को मताधिकार से वंचित करने का तर्क

1- मताधिकार का प्रयोग स्वस्थ व विवेकशील व्यक्ति करता है जबकि कैदी (जिन्होंने अपराध किया है) एक प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2- कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है, जिस प्रकार अपराधी, अपराध के माध्यम से दूसरों को अधिकार से वंचित करता है, तो उसे मताधिकार नहीं मिलना चाहिए।

3- मताधिकार मूल अधिकार नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार है और कैदी को कानून उल्लंघन की स्थिति में कानूनी अधिकार देना विरोधाभासी है।

कैदियों को मताधिकार देने के पक्ष में तर्क

1- भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या → बाद में कई निर्दोष साबित → अतः यह उनके साथ भेदभाव

2- सजा का आशय सुधार करना है और किसी प्रकार के अधिकार से वंचना उसमें समाज के प्रति रोष पैदा करती है।

3- वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्ति सभी लोगों की भागीदारी से संभव है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4 - मताधिकार के प्रयोग से सरकारें कैदियों की स्थिति में सुधार का प्रयास करेंगी जिससे जेलों में कम भीड़, under trial death की समस्या कम होगी।

लेकिन कैदियों के मताधिकार प्रयोग में कुछ चुनौतियां हैं —

1. वास्तविक आंकड़ों का अभाव
2. मतदान में भ्रष्टाचार की समस्या
3. जबरन किसी पक्ष में मतदान आदि

लेकिन इन समस्याओं को तकनीकी प्रयोग, सिविल सोसाइटी व सक्रिय न्यायपालिका व पुलिस प्रशासन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अतः इस पर सभी हितधारकों की सहमति से निर्णय लिया जाना चाहिए।

12. There are similarities and interactions between the affirmative action adopted by India and USA owing to similar historical injustices faced by their respective vulnerable groups. Discuss. **(250 words) 15**

भारत और यू. एस. ए. के सुभेद्य समूहों द्वारा सामना किए गए एकसमान ऐतिहासिक अन्याय के कारण, इनके द्वारा अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के बीच समानताएं हैं और इनका एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। चर्चा कीजिए।

सकारात्मक कार्रवाइयाँ वंचित समूह को मुख्यधारा में लाने के लिए नार्किक भेदभाव से संबंधित होती हैं।
जैसे - भारत में आरक्षण व्यवस्था

भारत और अमेरिका दोनों ही देश ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय शक्तियों से औपनिवेशिक शोषण से प्रभावित रहे जिसे समाज का एक वर्ग हाशिए पर चला गया।
जैसे - अमेरिका - मूल निवासी, रेड इण्डियन
- अश्वेत (दासों के रूप में लाए गए)
भारत - आदिवासी, अनुसूचित जातियां महिलाएँ आदि।

अत: समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका व भारत

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

की सरकारों ने कुछ ~~सकारात्मक~~ कार्रवाईयाँ प्रारंभ की।

अमेरिका में - डायवर्सिटी व्यवस्था

भारत में - आरक्षण व्यवस्था
- 5th & 6th schedule
- PESA Act आदि

दोनों के मध्य समानताएँ

1- दोनों में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान मानते हुए कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

2- दोनों ही व्यवस्थाओं में तार्किक भेदभाव को स्वीकारा गया है।

3- दोनों का उद्देश्य वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना।

अमेरिका में डायवर्सिटी सिस्टम में स्कूलों, नौकरियों में श्वेत, अश्वेत आदि विविध समूहों को रखा जाता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

है और ऐसा करने पर सरकार प्रोत्साहन भी देती है।

भारत में इसी से प्रभावित होकर शिक्षा व रोजगार में आरक्षण की सीटें नियत कर दी गई हैं।

किसी भी समाज का विकास सभी लोगों की सहभागिता से ही संभव है। भारत व अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप सामाजिक न्याय के लक्ष्य को लेकर चलते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Objections to domicile-based reservation in private sector jobs on the grounds of constitutional equality and freedom are misplaced. Critically discuss. **(250 words) 15**

संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति अनुचित है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

निजी क्षेत्र की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण राज्य में कार्यरत निजी कम्पनियों में स्थानीय निवासियों को रोजगार में वरीयता देने की मांग करता है। जैसे - हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में 75% अधिवास आधारित आरक्षण को लागू किया।

इस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा संवैधानिक समानता (Art. 14, 15, 16) व स्वतंत्रता (Art 19) के आधार पर न्यायालय में याचिका दायर की है।

निजी क्षेत्रक में अधिवास आधारित आरक्षण के लाभ

1- स्थानीय बेरोजगारी में कमी
2- राज्य के युवाओं में असंतोष में कमी
3- कुशल श्रमशक्ति का विकास होगा
4- अन्तर्राज्यीय आर्थिक विषमता में कमी तथा प्रवासन में कमी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5- जिस समाज के संसाधनों का कंपनी द्वारा उपयोग, उसी समाज को अधिक लाभ के सिद्धांत के अनुकूल।

चुनौतियाँ

1- कंपनी के लिए कुशल कार्यबल का अभाव।

2- अकुशल श्रमिकों को रखने की कानूनी बाध्यता

3- राज्य में कंपनियां निवेश करना कम देगी जो पुनः राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर तथा बेरोजगारी को बढ़ाएगा।

4- मूल अधिकारों का उल्लंघन - अनु. 19 - कहीं भी बसने, व्यापार करने की स्वतंत्रता
अनु - 16 - अवसरों की समानता

5- निवास आधारित आरक्षण लागू करने का अधिकार केवल संसद को।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6- राज्यों के बीच संघर्ष में वृद्धि और संघात्मक शासन तथा एकता-अखण्डता के लिए चुनौती।

आगे की राह

1- राज्य को अपने युवाओं के कौशल विकास की योजना पर ध्यान देना

2- बेहतर अवसंरचना के निर्माण द्वारा रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना

3- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार का अधिक निवेश आकर्षित करना

इस प्रकार निवास आधारित आरक्षण सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करेगा अतः समावेशी व कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. There have been arguments that sedition law is an attack on the very foundation of India's liberal democratic principles, as enshrined in the Constitution. Do you agree? **(250 words) 15**

ऐसा तर्क दिया जाता है कि राजद्रोह कानून भारत के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला है, जैसा कि संविधान में निहित हैं। क्या आप सहमत हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124A में राजद्रोह कानून का प्रावधान है जिसके अनुसार- सरकार के प्रति किसी प्रकार की हिंसा, घृणा, असंतोष या अप्रीति उत्पन्न करना राजद्रोह माना जाएगा।

उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला

1- असहमति लोकतंत्र का सार है और यह कानून असहमति को दबाने का प्रयास करता है।

2- सरकार की आलोचना के अभाव में सरकार में उत्तरदायित्व की भावना में कमी जो लोकतंत्र को कमजोर करती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3- अन्य ऐसे कारण जो इस कानून की अप्रासंगिकता सिद्ध करते हैं —

- औपनिवेशिक युग का कानून, संवैधानिक लोकतंत्र के अनुकूल नहीं।
- दोष सिद्धि दर अत्यन्त न्यून - 2016 से केवल 4 लोगों पर दोष सिद्ध
- विधि आयोग ने भी इसकी समाप्ति की अनुशंसा ~~की~~
- 'अप्रीति' जैसे शब्दों की अस्पष्ट व्याख्या के कारण दुरुपयोग।

लेकिन, कुछ कारणों से इसकी आवश्यकता भी महसूस की जा सकती है। केदारनाथ केस में SC ने इसे बनाए रखने का आदेश दिया क्योंकि

1- यह विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अवैध गतिविधियों से सुरक्षा
2- आंतकी व उग्रवादी गतिविधियों से

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुरक्षा जबकि भारत में नक्सलवाद, आतंकवाद आदि की समस्या है।

अतः समस्या कानून में नहीं बल्कि इसके प्रयोग में है। जैसा कि SC ने कन्हैया कुमार केस, केदारनाथ वाद में कहा कि –

- इसका प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों
- असहमति / आलोचना राजद्रोह नहीं है।

अतः इस पर सभी हितधारकों से विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लेना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Despite Government e-Marketplace facing certain challenges, it has brought about a significant improvement in the procurement of goods and services by various government agencies. Discuss. **(250 words) 15**

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा कुछ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, इन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण सुधार किया है। चर्चा कीजिए।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) सरकारी खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो सरकारी खरीद को त्वरित व पारदर्शी बनाता है।

GEM द्वारा खरीद में सुधार

1- इस पर विभिन्न विक्रेताओं की उपस्थिति के कारण प्रतिस्पर्धी मूल्य → अत: धन के अपव्यय में कमी।

2- सरकारी खरीद में गोपनीयता के स्थान पर पारदर्शी संस्कृति के विकास से भ्रष्टाचार में कमी।

3- सरकारी खरीद तीव्र, कुशल व प्रभावी हुई।

4- खरीदे गए उत्पादों की डिलेवरी की ट्रेकिंग करने की सुविधा उपलब्ध

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

GEM के समक्ष चुनौतियाँ

1- इस पर कुछ विक्रेताओं का स्वाधिकार जिससे अन्य को प्रवेश करने में कठिनाई।

2- अधिकांश MSME इस प्लेटफार्म पर विक्री करने में असमर्थ
- → आवश्यक क्षमता का अभाव
- → जागरूकता का अभाव

3- GEM में तकनीकी संबंधी समस्याएँ

4- कुशल पेशेवरों का अभाव

5- अभी भी सरकारी खरीद का एक हिस्सा GEM के बाहर से

GEM को अधिक सर्वसमावेशी व कुशल बनाकर e-Governance के प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जो सरकारी खरीद में पारदर्शिता, व तीव्रता लाकर सुशासन की प्राप्ति की दिशा में प्रमुख कदम सिद्ध होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. A reformed system of recruitment, training and evaluation needs to be put in place to take forward the development of a highly efficient and accountable civil service. Discuss in the context of India. **(250 words) 15**

अत्यधिक कुशल और जवाबदेह सिविल सेवा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन की एक संशोधित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारतीय लोककल्याणकारी राज्य में नागरिकों तक सेवा-प्रदायगी व सरकार की नीतियों को लागू करने में सिविल सेवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इन्हें स्टील फ्रेम की संज्ञा दी जाती है।

संसोधित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता

1- सिविल सेवा में व्याप्त कमियाँ

- अनु. 311 के कारण अत्यधिक सुरक्षा से निष्क्रियता की स्थिति
- नवाचारों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण
- आभिजात्यवादी व शहरी मानसिकता
- सेवा भावना, समर्पण, वस्तुनिष्ठता जैसे नैतिक मूल्यों की कमी
- पारदर्शिता, उत्तरदायित्व के अभाव से उत्पन्न भ्रष्टाचार की समस्या

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2- सेवाओं की बदलती प्रकृति
- निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय देशों से तुलना के आधार पर नागरिकों द्वारा बेहतर गुणवत्ता व शीघ्र रूप से सेवाओं की मांग
- विशेषज्ञता की बढ़ती मांग

3- पदोन्नति प्रक्रिया समय आधारित जिससे लोकसेवकों कार्य के प्रति उत्साह नहीं।

4- सोशल मीडिया के कारण अनामिता व राजनीतिक तटस्थता जैसे मूल्यों की कमी।

अत: इसके लिए सिविल सेवा में भर्ती, प्रशिक्षण व मूल्यांकन में निम्न सुधार किए जाने चाहिए-

1- भर्ती प्रक्रिया - उच्च नैतिक मूल्य वाले सिविल सेवकों की भर्ती
- भर्ती प्रक्रिया में अधिक वस्तुनिष्ठ लाना

2- प्रशिक्षण - कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स की समुचित प्रशिक्षण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- व्यक्ति की रुचि के अनुरूप उसे विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण द्वारा विशेषज्ञ बनाना
- विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं व वास्तविक धरातल पर प्रशिक्षण

मूल्यांकन - 360° मूल्यांकन पद्धति
- मूल्यांकन द्वारा परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन
- वित्तीय संपत्ति का मूल्यांकन

हाल ही में सरकार द्वारा इस संबंध में मिशन कर्मयोगी आरंभ किया है भर्ती, मूल्यांकन, प्रशिक्षण व्यवस्था में IGOT प्लेटफार्म के माध्यम से कुशल सिविल सेवा के निर्माण पर केन्द्रित है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Despite initiatives taken by the Indian government to achieve critical goals in the education sector, major interventions are required to tackle learning poverty as well as the persisting inequalities. Discuss. **(250 words) 15**

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलों के बावजूद, लर्निंग पॉवर्टी (अधिगम निर्धनता) के साथ-साथ विद्यमान असमानताओं से निपटने के लिए बड़े हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

लर्निंग पॉवर्टी से आशय 10वर्ष के बच्चे द्वारा उसके लिए निर्धारित पाठ को न पाने ~~सक्ष~~ से है।

ASER की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 3 में केवल 67% बच्चे निर्धारित पाठ पढ़ पाए तथा कक्षा 1 में 41% बच्चे दो अंको की संख्याओं को पहचान पाए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा आरंभ की गई पहले

1. सर्व शिक्षा अभियान
2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - माध्यमिक स्तर पर GER बढ़ाने हेतु
3. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4- मिड-डे मील – पोषण व कक्षा में उपस्थिति में सुधार हेतु

5- PMG DISHA तथा 'स्वयं' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा

6- ग्रामीण स्कूलों में साइकिल, टैबलेट, आदि का वितरण

। उपर्युक्त पहलों के बावजूद लर्निंग पॉवर्टी व असमानता की समस्या क्योंकि

1- स्कूलों में शिक्षकों व बच्चों की कम उपस्थिति

2- आवश्यक अवसंरचना का अभाव
  - → टायलेट, क्लासरूम आदि
  - → डिजिटल अवसंरचना

3- पाठ्यक्रम का अद्यतन न होना

4- शिक्षकों में कौशल का अभाव, 14% शिक्षक उनके लिए निर्धारित कक्षा के सवाल हल नहीं कर पाए

5- गरीबी, बेरोजगारी के कारण बच्चों की अधिगम क्षमता प्रभावित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस दिशा में उठाए जा सकने वाले कदम

1- शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल तथा स्कूलों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित (बायोमीट्रिक्स प्रणाली)

2- पाठ्यक्रम को समय-समय पर अपडेट करना

3- ऑडियो-वीडियो क्लासेस के माध्यम से अधिगम क्षमता में वृद्धि

4. नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन

5- बेहतर व आधुनिक अवसंरचना

डॉ० राधाकृष्णन के अनुसार स्वस्थ व शिक्षित बच्चे बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। अतः उन पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. In light of the burgeoning burden of both communicable and non-communicable diseases, there is a need to revamp the public health surveillance system in India. Discuss. **(250 words) 15**

संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों के बढ़ते बोझ के आलोक में, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

रोगों को उनकी प्रसार क्षमता के आधार पर दो भागों में बाँटा जाता है -

रोग

- संचारी रोग
  - ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होते है
  - जैसे - टीबी, जुकाम, कोविड-19
- गैर - संचारी रोग
  - उनका सामान्यत: प्रसार नहीं होता है
  - जैसे - कैंसर, डायबिटीज आदि

वर्तमान में इन रोगों की अधिकता से व्यक्ति पर out of pocket expenditure में वृद्धि हो रही है जिससे वह गरीबी के लिए अधिक सुभेद्य हो जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

① आवश्यक अवसंरचना की कमी
→ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव
→ सीमित रोगी डॉक्टर अनुपात
1:1456 (WHO 1:1000)
→ अपर्याप्त बेड : सार्वजनिक अस्पतालों में 1 लाख जनसंख्या पर 22 बेड (औसत)

② स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच
→ जागरूकता की कमी
→ गरीबी - बेरोजगारी
→ अंधविश्वास व पारंपरिक चिकित्सा पर बल

③ विषम अनुपात में स्वास्थ्य सेवाएँ
→ 70% डॉक्टर
→ 75% मेडीकल
→ 60% हॉस्पीटल
] शहरी क्षेत्र में

④ निम्न स्तरीय प्राथमिक व द्वितीयक स्वास्थ्य अवसंरचना → 5% PHCs में डॉक्टर नहीं
→ 60% PHCs में एक डॉक्टर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) लगभग 15 - 20% जनता के पास स्वास्थ्य बीमा।

सुधार के लिए आवश्यक कदम

- आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना आदि का बेहतर क्रियान्वयन
- स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि GDP का 2.5% (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति)
- PHCs, SHCs में सुधार
- निजी क्षेत्र व NGO की सहायता
- अवसंरचना उन्नयन तथा निर्माण
- ANM व आशा वर्कर द्वारा गाँव में स्वास्थ्य जागरूकता
- डॉक्टरों का प्रशिक्षण

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ SDG-3 की प्राप्ति तथा बेहतर आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करेंगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The repercussions of the ongoing economic crisis in Sri Lanka extend beyond its borders. Discuss with specific reference to India. Also, mention the steps that India has taken to assist Sri Lanka tide over the crisis.

(250 words) 15

श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे भी पड़ रहा है। भारत के विशिष्ट संदर्भ में विवेचना कीजिए। साथ ही, उन कदमों का भी उल्लेख कीजिए जो भारत ने इस संकट से निपटने में श्रीलंका की सहायता के लिए उठाए हैं।

श्रीलंका में वित्तीय कुप्रबंधन व अत्यधिक विदेशी ऋण के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है जिससे वहां अत्यधिक महंगाई, विरोध-प्रदर्शन आदि की समस्या देखने को मिल रही है।

श्रीलंका के आर्थिक संकट का प्रभाव

श्रीलंका में	भारत पर
1- देश की आर्थिक दशा खराब	1- प्रवासियों की संख्या बढ़ने की संभावना
2- महंगाई में वृद्धि	2- चीन द्वारा ऋण देकर IOR में अपनी उपस्थिति बढ़ाना
3- नागरिक जीवन अस्तव्यस्त	3- भारत की परियोजनाएं प्रभावित
4- राजनीतिक अस्थिरता व विरोध-प्रदर्शन	
5- मानवाधिकारों की समस्या आदि	

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5- पड़ोसी प्रथम नीति
के अनुरूप मदद देने
का दबाव

भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास

1- 1400 mn की Line of credit

2- तेल व पेट्रोलियम के लिए
credit दिया ।

3- खाद्यान्न की आपूर्ति की

4- विश्व के अन्य देशों से
श्रीलंका को ऋण दिलाने की
अपील

श्रीलंका, IOR में भारत की
स्थिति को मजबूत करने तथा
चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने
के लिए उसे मदद देना आवश्यक

है जो 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India is a reliable partner in the Indian Ocean Region and can take on the role of being the net security provider in the region. Discuss.

(250 words) 15

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार है और इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता होने की भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिए।

भारत के 70% व्यापार मूल्य के अनुसार व 90% मात्रा के अनुसार समुद्री मार्ग से होता है जिससे IOR का महत्व भारत के लिए अत्यधिक है।

भारत IOR में एक विश्वसनीय भागीदार है तथा इसे मुक्त, समावेशी बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए इसने QUAD में भाग लिया और IOR के संबंध में अपने दृष्टिकोण का परिचय दिया

→ IORA का एक प्रमुख सदस्य जो इस क्षेत्र के देशों के मध्य सहयोग व समन्वय पर कार्य करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निवल सुरक्षा प्रदाता बनने के चार आयाम होते है

सैन्य सुरक्षा	प्रशिक्षण
सैन्य अभ्यास	सैन्य तैनाती

~~→ माल~~

→ भारत द्वारा IOR में सैन्य अभ्यास जैसे मालाबार, INSLN आदि किए जाते है।

→ मालदीव, श्रीलंका व अन्य देशों को सैन्य प्रशिक्षण व सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है।

⇒ चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रयासरत है।